शीर्ष 500 निजी कंपनियों में रिलायंस अव्वल

आईपीएल की पांच टीमें सूची में पहली बार

नई दिल्ली, 24 जून. देश में वर्ष 2025 के लिए हुरुन इंडिया और बर्गंडी की निजी क्षेत्र की शीर्ष 500 कंपनियों की '500 मोस्ट वैल्युएबल नॉन-स्टेट-रन कंपनियां इन इंडिया' सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार पांचवें वर्ष इस सूची में शीर्ष पर है और सूची में पहली बार आईपीएल क्रिकेट की फ्रैंचाइजी फर्मों ने स्थान बनाया है, जो क्रिकेट को देश के कॉरपोरेट जगत के लिए कमाई की एक नयी उभरती संपत्ति के रूप में दर्शाता है.

एक्सिस बैंक की बर्गंडी प्राइवेट और हुरुन इंडिया द्वारा तैयार की जाने वाली इस वार्षिक सूची में इस बार स्थान पाने वाली कंपनियों का कुल बाजार मूल्य 3.4 लाख करोड़ डॉलर हो चुका है, जो दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बराबर है. रिलायंस इंडस्ट्रीज ने लगातार पांचवें वर्ष देश की शीर्ष निजी कंपनी के रूप में पहला स्थान बरकरार रखा है, हालांकि प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. सूची दर्शाती है कि क्रिकेट अब कॉरपोरेट पूंजी का रूप ले रहा है. इस सूची में पहली बार आईपीएल की पांच फ्रेंचाइज़ियों को स्थान दिया गया है. इनमें कोलकाता नाइट राइडर्स 20,850 करोड़ रुपये की अनुमानित हैसियत के साथ 270 वें स्थान पर है. चेन्नई सुपर किंग्स 19,550 करोड़ रुपये की हैसियत के साथ 285 वें स्थान पर है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16,700 करोड़ रुपये के साथ 330 वें स्थान पर है, राजस्थान रॉयल्स 15,700 करोड़ रुपये की हैसियत के साथ 343 वें स्थान पर है और पंजाब किंग्स 14,050 करोड़ रुपये की हैसियत के साथ 390वें स्थान पर है. रिपोर्ट में कहा गया है, 'यह खेलों को एक नई उभरती हुई बाजार संपत्ति के रूप में स्थापित करता है.' वर्ष 2025 में इन 500 में से केवल 198 कंपनियों के मूल्य में वृद्धि दर्ज की गई. इस सूची के पांचवें संस्करण में इस बार 94 नई प्रविष्टियां हैं, जिनका संयुक्त मूल्य 18.45 लाख करोड़ रुपये है. यह देश में उद्यमशीलता के विस्तार को दर्शाती है.

> वर्ष 2021 के बाद से सूची की एक-तिहाई से अधिक कंपनियां बदल चुकी हैं, जो देश के कॉरपोरेट क्षितिज में तीव्र बदलावों को दर्शाता है. व्यवसायिक जगत के अवसर अब महानगरों से निकलकर छोटे शहरों तक पहुंचने लगे हैं. राजकोट, बीकानेर, कुंभकोणम और राजनांदगांव जैसे शहरों की कंपनियां सूची में शामिल हुई हैं, जो टियर-2 और टियर-3 शहरों के उदय को दर्शाती हैं.

जेट फ्यूल संकट से हवाई सफर होगा महंगा

25 प्रतिशद बढ़ सकते टिकट दाम

जेट फ्यूल की उपलब्धता को सीमित कर दिया

नई दिल्ली, 25 जून. वैश्विक एविएशन सेक्टर एक बार फिर लागत संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकिंजी की रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में हवाई यात्रा 25 प्रतिशत तक महंगी हो सकती है.

इस संभावित बढ़ोतरी के पीछे सबसे बड़ा कारण जेट फ्यूल की कीमतों में लगातार हो रहा इजाफा और सप्लाई में आई बाधाएं हैं. दुनिया के कई हिस्सों में जारी भू-राजनीतिक तनाव ने ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया है. इसके साथ ही रिफाइनरी उत्पादन में आई कमी ने भी जेट फ्यूल की उपलब्धता को सीमित कर दिया है. इन दोनों कारणों का संयुक्त प्रभाव एयरलाइंस कंपनियों की लागत संरचना पर साफ दिखाई देने लगा है. मैकिंजी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया कि एविएशन इंडस्ट्री में फ्यूल लागत का हिस्सा बेहद महत्वपूर्ण होता है. औसतन किसी भी एयर टिकट की कीमत का लगभग 30 प्रतिशत केवल जेट फ्यूल पर निर्भर करता है. ऐसे में फ्यूल की कीमतों में मामूली वृद्धि भी टिकट दरों पर बड़ा असर डाल सकती है. कई देशों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अपने जेट फ्यूल रिजर्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं. हालांकि, इससे वैश्विक बाजार में आपूर्ति और मांग का संतुलन और अधिक प्रभावित हो सकता है. अगर यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो एयरलाइंस कंपनियों को या तो अपने ऑपरेशनल मॉडल में बदलाव करना होगा या फिर बढ़ी हुई लागत का बोझ यात्रियों पर डालना होगा.

> वर्तमान समय में जब अंतरराष्ट्रीय यात्रा की मांग फिर से तेजी पकड़ रही है, ऐसे में टिकट कीमतों में संभावित बढ़ोतरी यात्रियों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकती है. खासकर मिडिल क्लास और बजट ट्रैवलर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है.

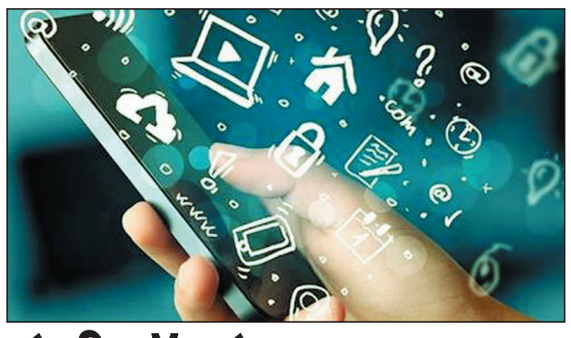

टेलीकॉम डेटा पर सरकार का बड़ा फैसला

विदेशी सर्वर पर डेटा भेजने पर रोक

भारत में डेटा सेंटर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा

बेंगलुरु, 25 जून. भारत में डिजिटल सुरक्षा और टेलीकॉम सेक्टर के संचालन को लेकर सरकार ने एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है. दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नए नियमों के तहत अब देश के सभी टेलीकॉम ऑपरेटरों को अपने यूजर्स का पूरा डेटा भारत के भीतर ही स्टोर करना अनिवार्य होगा.

इसमें कॉल डिटेल रिकॉर्ड, इंटरनेट उपयोग, लोकेशन डेटा और अन्य डिजिटल लॉग्स शामिल हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी परिस्थिति में यह डेटा देश की सीमाओं के बाहर नहीं भेजा जा सकेगा और न ही इसे किसी विदेशी एजेंसी या संस्था के साथ साझा किया जाएगा. इस फैसले का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की डिजिटल प्राइवेसी को मजबूत करना और डेटा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है.

हाल के वर्षों में डेटा लीक और साइबर सुरक्षा को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि डेटा लोकलाइजेशन से न केवल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि भारत में डेटा सेंटर उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा.

> नए नियमों के तहत टेलीकॉम सेक्टर में लंबे समय से चला आ रहा लाइसेंस राज भी समाप्त कर दिया गया है. अब कंपनियों को विभिन्न अनुमतियों और प्रक्रियाओं के लिए जटिल नौकरशाही से गुजरना नहीं पड़ेगा. अधिकांश अनुमोदन प्रक्रियाएं अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकेंगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी. यह सुधार टेलीकॉम सेक्टर को अधिक पारदर्शी, कुशल और निवेश-हितैषी बनाएगा. इससे न केवल बड़ी कंपनियों को लाभ मिलेगा, बल्कि छोटे और नए ऑपरेटरों के लिए भी बाजार में प्रवेश आसान होगा.

इबोला प्रभावित देशों पर नई सख्ती

एयर सुविधा पोर्टल फिर से सक्रिय

नई दिल्ली , 25 जून. इबोला वायरस का प्रकोप मध्य और पूर्वी अफ्रीका तक सीमित है. हालांकि, फ्रांस भी अलर्ट मोड पर आ चुका है. इबोला से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों को लेकर भारत अलर्ट हो गया. इबोला से प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा पोर्टल एक्टिव है.

यात्री उतरने से पहले जरूरी सेल्फ-डिक्लेरेशन फॉर्म आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इससे पहले पेपर-बेस्ड प्रक्रिया फॉलो की जा रही थी. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा इबोला को अंतरराष्ट्रीय चिंता वाली सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति (पीएचईआईसी) घोषित किए जाने के बाद से यह व्यवस्था लागू है. इसके तहत प्रवेश बिंदुओं (एयरपोर्ट, बंदरगाह आदि) पर स्वास्थ्य निगरानी को मजबूत करने के साथ-साथ यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के उपाय भी किए गए हैं. फ्रांस ने पांच ऐसे लोगों की पहचान की है और उन्हें आइसोलेट किया है जो इबोला वायरस से संक्रमित हो सकते हैं. ये लोग एक डॉक्टर के साथ फ्लाइट में सफर कर रहे थे, जिसका वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया था.

शेयर बाजार की हुई मजबूत शुरुआत

400 अंक चढ़ा सेंसेक्स

24,100 के पार हुआ निफ्टी

नई दिल्ली , 25 जून. गुरुवार की सुबह भारतीय शेयर बाजार ने मजबूती के साथ कारोबार की शुरुआत की, जिससे निवेशकों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई.

बीते सत्र में हुई तेजी के बाद भी बाजार में खरीदारी का सिलसिला जारी रहा और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों प्रमुख सूचकांकों ने मजबूती दिखाई. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और स्थिर आर्थिक संकेतों ने घरेलू बाजार को सहारा दिया. सुबह 09:16 बजे जैसे ही ओपनिंग बेल बजी, बीएसई सेंसेक्स ने 367.18 अंक यानी 0.47% की बढ़त के साथ 77,358.40 के स्तर पर कारोबार की शुरुआत की. इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 104.75 अंक यानी 0.44% की तेजी के साथ 24,126.40 के स्तर पर खुला.

शुरुआती मिनटों में ही बाजार में खरीदारी का दबाव इतना मजबूत रहा कि सेंसेक्स 400 अंकों से अधिक की बढ़त दिखाने लगा. बाजार की इस तेजी में कई बड़े सेक्टर्स ने अहम भूमिका निभाई. विशेष रूप से आईटी सेक्टर में मजबूती देखने को मिली, जहां एचसीएल टेक जैसे दिग्गज शेयरों में लगभग 2% की बढ़त दर्ज की गई.

इसके साथ ही एविएशन सेक्टर की प्रमुख कंपनी इंडिगो के शेयरों में भी करीब 2% की तेजी देखी गई, जिसने निवेशकों के भरोसे को और मजबूत किया.

अंत्योदय अन्न योजना में बड़े बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली, 25 जून. सरकार देश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. इसके तहत अंत्योदय अन्न योजना में व्यापक बदलाव की तैयारी की गई है, जो देश के सबसे गरीब और वंचित तबके को सीधे प्रभावित करेगा. यह योजना उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करते हैं और जिनके पास आय के सीमित या बिल्कुल भी साधन नहीं हैं. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है. इस प्रस्ताव का उद्देश्य मौजूदा राशन वितरण प्रणाली में मौजूद खामियों को दूर करना और इसे अधिक पारदर्शी, संतुलित और जरूरत आधारित बनाना है.

एआई प्लस नोवा 2 प्रो और नोवा 2 नियो की बिक्री शुरू

नवभारत, जबलपुर। एआई प्लस स्मार्टफोन ने अपने नए 5जी स्मार्टफोन, नोवा 2 प्रो और नोवा 2 नियो की बिक्री शुरू कर दी है। ये दोनों डिवाइस आज 26 जून को दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे। बिक्री के पहले दिन नोवा 2 नियो का 4जीबी+128जीबी वेरिएंट 12,999 रुपए और 6जीबी+128जीबी वेरिएंट 13,999 रुपए में मिलेगा, जबकि नोवा 2 प्रो का 6जीबी+128जीबी वेरिएंट 14,999 रुपए और 8जीबी+128जीबी वेरिएंट 16,999 रुपए से शुरू होगा। सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए का बैंक ऑफर भी मिलेगा। सीईओ

माधव सेठ ने कहा कि ये फोन कम बजट में बेहतर परफॉर्मेंस, बड़ी बैटरी और प्राइवेसी देने के लिए बनाए गए हैं।

नोवा 2 नियो : रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तैयार

नोवा 2 नियो स्मार्टफोन मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट और 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाले 6.745 इंच डिस्प्ले के साथ आता है। यह फोन एंड्रॉइड 16 पर आधारित नेक्स्टक्वांटम ओएस पर चलता है। इसके अलावा, फोन में पूरे दिन चलने वाली 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी, 18 वॉट की चार्जिंग और धूल व पानी से सुरक्षा के लिए आईपी 65 रेटिंग मिलती है।

नोवा 2 प्रो : बेहतर परफॉर्मेंस और क्रिएटिव काम

नोवा 2 प्रो में ज्यादा ताकतवर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 7100 चिपसेट और 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला 6.9 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया गया है। प्राइवेसी फीचर्स के साथ यह फोन भी एंड्रॉइड 16 सॉफ्टवेयर पर काम करता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 48 एमपी का मुख्य कैमरा, 8एमपी का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 13 एमपी का फ्रंट कैमरा शामिल है।

ट्रेंट को नई ऊंचाई देकर चेयरमैन पद छोड़ेंगे नोएल टाटा

मुंबई, 25 जून. टाटा समूह की रिटेल शाखा ट्रेंट लिमिटेड में एक बड़े नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी शुरू हो गई है. कंपनी के चेयरमैन नोएल टाटा ने 23 जून को आयोजित 74वीं वार्षिक आम बैठक में संकेत दिया कि यह चेयरमैन के रूप में उनकी आखिरी एजीएम होगी. उनके इस बयान के बाद निवेशकों, बाजार विशेषज्ञों और उद्योग जगत में कंपनी के अगले नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. नोएल टाटा का नाम ट्रेंट की विकास यात्रा के साथ गहराई से जुड़ा रहा है.

भारत ने सिंगापुर भेजा पहला समुद्री आम निर्यात

नई दिल्ली, 25 जून. ताजे फलों के निर्यात को बढ़ावा देते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्यरत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने केंद्रीय उपोष्णकटिबंधीय बागवानी संस्थान, लखनऊ के सहयोग से सिंगापुर को बंगानापल्ली आमों का पहला व्यावसायिक समुद्री शिपमेंट सफलतापूर्वक भेज दिया है. आंध्रप्रदेश के इस बेहद रसीले और मीठे आम की किस्म बंगानापल्ली के पांच टन की यह

खेप 11 जून को रवाना हुई और वह 24 जून को सिंगापुर पहुँची.

यह सफल प्रयास भारत के बागवानी उत्पादों के लिए कम लागत वाली और टिकाऊ निर्यात व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदेशों में भारतीय आमों की बाजार पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है.

समाचार विशेष

संसदीय बोर्ड में फड़नवीस या योगी?

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी में फैसला करने वाली सबसे बड़ी बॉडी संसदीय बोर्ड है. हालांकि सबको पता है कि चाहे कांग्रेस की सीडब्लुसी हो या भाजपा का संसदीय बोर्ड, फैसला ऊपर से दो या तीन लोगों को ही करना होता है. फिर भी भाजपा के संसदीय बोर्ड का सदस्य होना एक समय बहुत बड़ी बात मानी जाती थी. पार्टी के सबसे बड़े नेता ही इसके सदस्य होते थे. पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षों को इसमें रखा जाता था.

हालांकि नितिन गडकरी को इसमें से हटा दिया गया है. अभी 12 सदस्य हैं, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और संगठन महामंत्री पदेन सदस्य के तौर पर हैं. इनके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा पूर्व अध्यक्ष के तौर पर हैं. बाकी लोगों में एक बीएस येदियुरप्पा और सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद वहां सांत्वना के तौर पर एडजस्ट किया गया था. लेकिन अन्य चार लोगों को पता नहीं था कि उनको क्यों संसदीय बोर्ड में रखा गया है.

इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव, के लक्ष्मण और सत्यनारायण जटिया को भी संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया था. अब कहा जा रहा है कि 12 सदस्यों की इस बॉडी से कई लोगों को हटाया जा सकता है और नए चेहरे लाए जा सकते हैं.

> नए चेहरों में सबसे ज्यादा नजर देवेंद्र फड़नवीस और योगी आदित्यनाथ पर होगी. ध्यान रहे अभी 16 राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं लेकिन किसी को इसमें नहीं रखा गया है. एक समय मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह चौहान संसदीय बोर्ड के सदस्य होते थे. अगर देवेंद्र फड़नवीस को संसदीय बोर्ड में जगह मिलती है तो यह मैसेज जाएगा कि वे योगी आदित्यनाथ से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. ध्यान रहे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं. सो, योगी या फड़नवीस या दोनों की अटकलें लगाई जा रही हैं. वैसे फड़नवीस अभी केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं. केंद्रीय चुनाव समिति में संसदीय बोर्ड के 12 सदस्यों के अलावा सिर्फ फड़नवीस, भूपेंद्र यादव और महिला मोर्चा की अध्यक्ष वनाथी श्रीनिवासन ही सदस्य हैं.

क्या एनडीए में शामिल होगी डीएमके?

मुस्लिम लीग के अलग होने के बाद तेज हुई अटकलें, 360 के आंकड़े पर नजर

चेन्नई. तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़े घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति की चर्चाओं को भी तेज कर दिया है. द्रविड़ मुनेत्र कषगम (डीएमके) की वर्षों पुरानी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आधिकारिक तौर पर डीएमके नीत सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस से अलग होने का फैसला कर लिया है.

इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अब तक विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही डीएमके, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) का दामन थाम सकती है.

यदि डीएमके एनडीए में शामिल होती है, तो लोकसभा में उसके 22 सांसदों का समर्थन मिलने से मोदी सरकार के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी 360 सीटों का आंकड़ा पार करना आसान हो सकता है. इससे परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने में केंद्र सरकार को बड़ी ताकत मिल सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, चेन्नई में आयोजित अपनी जनरल काउंसिल की बैठक में आईयूएमएल ने 14 प्रस्ताव पारित किए, जिनमें डीएमके गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव भी शामिल था. पार्टी ने कहा कि विधानसभा चुनावों के बाद उसने मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली तमिलगा वेत्री कझगम सरकार को समर्थन दिया था और मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में डीएमके गठबंधन में बने रहना संभव नहीं है. लीग अध्यक्ष केएम खादर मोहिदीन ने कहा कि पार्टी को विधानसभा, लोकसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में जो सफलता मिली, उसमें डीएमके गठबंधन की अहम भूमिका रही.

क्यों हो रही आनंदी बेन को बदलने की चर्चा?

लखनऊ. अचानक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को बदले जाने की चर्चा शुरू हो गई है. कहा जा रहा है कि राज्यपाल के तौर पर वे 10 साल पूरे करने जा रही हैं. उत्तर प्रदेश में ही उनको सात साल होने जा रहे हैं. वे 29 जुलाई 2019 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थीं.

उससे पहले वे मध्य प्रदेश की राज्यपाल थीं. नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वे गुजरात की मुख्यमंत्री बनी थीं. वहां से हटने के थोड़े दिन बाद वे राज्यपाल बनीं. अगले साल उत्तर प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव है. ऐसे में उनके बदलाव की चर्चा अनायास तो नहीं हो सकती है.

कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के किसी बड़े मंत्री को सरकार से हटाया जाएगा और उनको सांत्वना के तौर पर उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाएगा. लेकिन आनंदी बेन पटेल का क्या होगा? यूपी के चुनाव में गैर यादव पिछड़ी जातियों को क्या संदेश जाएगा और क्या उनके गुजरात लौटने से वहां की राजनीति में एक नया शक्ति केंद्र नहीं बनेगा? यूपी के अलावा कुछ और राज्यों में राज्यपाल बदले जाने की चर्चा है. हालांकि ज्यादातर राज्यपाल अपेक्षाकृत नए हैं. सिर्फ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को इस साल जुलाई में सात साल और कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को जुलाई में पांच साल होने जा रहे हैं. प्रशासकों और उप राज्यपालों में कुछ लोगों के कार्यकाल पूरे हो गए हैं. इसलिए कोई व्यापक बदलाव होगा, यह नहीं कहा जा सकता है.

विशेष | **क्या जाट-मुस्लिम गठबंधन की जगह ले रहा है नया सामाजिक समीकरण?**

शेखावाटी की राजनीति में बदलते समीकरण

सीकर. राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की राजनीति लंबे समय से सामाजिक और जातीय समीकरणों के आधार पर आकार लेती रही है. कभी स्वतंत्र पार्टी के प्रभाव और बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों के उभार के बीच यहां कई सामाजिक गठबंधन बने और बदले.

अब क्षेत्र में एक बार फिर राजनीतिक समीकरणों में बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि लंबे समय तक प्रभावी रहे जाट-मुस्लिम राजनीतिक तालमेल में बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं, जबकि कुछ समूहों द्वारा राजपूत-मुस्लिम सामाजिक एवं राजनीतिक संवाद को मजबूत करने के प्रयास भी चर्चा में हैं.

शेखावाटी क्षेत्र में आजादी के बाद एक समय ऐसा था जब पूर्व राजघरानों और स्वतंत्र पार्टी की राजनीति का प्रभाव काफी मजबूत था. उस दौर में मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा स्वतंत्र पार्टी के साथ जुड़ा रहा. वर्ष 1967 में फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र से आलम अली खान स्वतंत्र पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए थे. वहीं 1972 में मंडावा क्षेत्र से स्वतंत्र पार्टी उम्मीदवार एजाजनबी खान ने भी उल्लेखनीय चुनावी मुकाबला किया था. उस समय कुछ क्षेत्रों में राजपूत और मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक सहयोग देखा गया. बाद के वर्षों में राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आया. जनता पार्टी के दौर और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद राजस्थान में नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे. भैरोंसिंह शेखावत के नेतृत्व में भाजपा को राजपूत समाज का मजबूत समर्थन मिलने लगा. दूसरी ओर, लोकदल और कांग्रेस जैसे दलों के साथ जाट और मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव बढ़ा और धीरे-धीरे जाट-मुस्लिम राजनीतिक समझ क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण पहचान बन गई.

राजपूतों के साथ मुस्लिम प्रतिनिधियों की भागीदारी

दूसरी ओर, झुंझुनूं जिले के झाझड़ गांव से जुड़े इंजीनियर महावीर सिंह शेखावत भी पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक स्तर पर सक्रिय दिखाई दिए हैं. उन्होंने विभिन्न समुदायों के बीच संवाद और भागीदारी के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए हैं. उनके नेतृत्व में आयोजित कुछ सम्मेलनों में राजपूत समाज के साथ मुस्लिम प्रतिनिधियों की भागीदारी भी देखने को मिली. इससे क्षेत्र में संभावित नए सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा तेज हुई है.